www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 157 | जौनपुर बुधवार, 21 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

तमिलनाडु विधानसभा में जोरदार हंगामा

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा का मंगलवार का सत्र उस समय भारी विवाद में बदल गया, जब राज्यपाल आर एन रवि ने उद्घाटन भाषण देने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर लिया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया और कार्यवाही के दौरान उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया, जिससे वह अपनी बात नहीं रख सके। सदन से बाहर निकलने के बाद राज्यपाल रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा– मैं निराश हूं। राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे भाषण में बार–बार बाधा डाली गई। उनके इस कदम से विधानसभा के भीतर तीखी बहस छिड़ गई।विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने राज्यपाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें सदन की परंपराओं, नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी। अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही तय प्रक्रिया के तहत चलती है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए।घटना के कुछ घंटों बाद राजभवन की ओर से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया कि राज्यपाल को बार–बार बोलने से रोका गया और उनका माइक्रोफोन जानबूझकर बंद किया गया। बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य में दलितों पर अत्याचार और दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं जैसे गंभीर मुद्दों को राज्यपाल के अभिभाषण में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।

साइना नेहवाल ने किया रिटायरमेंट का ऐलान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में वह इस खेल को जारी नहीं रख पाएंगी। लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी मैच 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था। बीते करीब ढाई–तीन साल से वह प्रोफेशनल बैडमिंटन में नजर नहीं आई हैं। घुटना उनका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से वह काफी समय से बैडमिंटन कोर्ट से दूर थीं।35 वर्षीय साइना नेहवाल भले ही बैडमिंटन कोर्च से दूर थीं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब एक पॉडकास्ट में साइना नेहवाल ने कहा, ''मैंने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं।'' नेहवाल ने कहा कि यह फैसला उनके घुटने की गंभीर खराबी की वजह से लिया गया, जिसकी वजह से लगातार हाई– इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना नामुमकिन हो गया था।

मुख्यमंत्री योगी ने बढ़ाया धान क्रय लक्ष्य, किसानों को मिली बड़ी राहत

मीरजापुर, (संवाददाता)। किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए धान क्रय केंद्रों के लक्ष्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरजापुर जनपद के लिए 37 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त धान क्रय का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय पूर्व मंत्री एवं मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के विशेष आग्रह और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है। विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने 19 जनवरी को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मड़िहान विधानसभा सहित जनपद के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बड़ी मात्रा में धान की खरीद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनका धान नहीं खरीदा जा सका है। इससे किसानों में चिंता का माहौल है और वे धान क्रय अवधि व लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए। विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने मंगलवार को कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी किसान का धान बिना खरीदे न रहे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि धान क्रय प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संचालित की जाए, ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस फैसले पर विधायक ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय हजारों किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य बढ़ने की खबर से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है।

'जब व्यवस्था सुचारू हो जाए, तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए : नितिन गडकरी

नागपुर, (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अगली पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की खुलकर वकालत करते हुए कहा कि जब किसी संस्था, संगठन या व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलने लगे, तो पुरानी पीढ़ी को स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ पीढ़ियों में बदलाव जरूरी है और नई पीढ़ी को नेतृत्व का अवसर देना ही स्वस्थ परंपरा है। गडकरी यह बात विदर्भ–खासदार औद्योगिक महोत्सव के संदर्भ में कह रहे थे, जिसकी परिकल्पना उन्होंने स्वयं की थी। इस महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा किया गया है। गडकरी एआईडी के मुख्य मार्गदर्शक भी हैं।अपने संबोधन में गडकरी ने कहा, "आशीष काले ने युवा पीढ़ी को 'एडवांटेज विदर्भ' पहल में शामिल किया है। मेरा मानना है कि धीरे–धीरे पीढ़ी में भी बदलाव आना चाहिए।" उन्होंने व्यक्तिगत संदर्भ देते हुए कहा, "आशीष के पिता मेरे मित्र हैं। अब हमें धीरे–धीरे सेवानिवृत्त होना चाहिए और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए।" गडकरी के इस बयान को केवल औद्योगिक संगठनों तक सीमित न मानकर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।गडकरी ने जानकारी दी कि नागपुर में छह से आठ फरवरी के बीच आयोजित होने वाला एडवांटेज विदर्भ एक्सपो अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विदर्भ क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मजबूत मंच बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली उद्यमी हैं।

बिहार में जमीन माप प्रक्रिया होगी तेज, पारदर्शी और समयबद्ध : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना, (संवाददाता)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन माप प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से 'सात निश्चय–3 (2025–30)' कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके सातवें निश्चय 'सबका सम्मानदृजीवन आसान' का मूल उद्देश्य आम नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जमीन मापी के लिए आवेदन देने के बाद प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग जाता है। इससे न केवल लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि समय पर मापी नहीं होने के कारण भूमि विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि मापी व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने आगे बताया कि 31 जनवरी 2026 तक विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर जमीन मापी से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत अविवादित जमीन माप के लिए शुल्क जमा होने के अधिकतम 7 कार्य दिवस के भीतर माप सुनिश्चित की जाएगी।

दिल्ली में अब हर इमरजेंसी का एक ही नंबर 112 : सीएम रेखा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, त्वरित और तकनीक–सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अब दिल्ली में किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति में अलग–अलग हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। किसी भी तरह की आपात स्थिति में सिर्फ 112 डायल करने पर तेजी से मदद पहुंचेगी। इसकी शुरुआत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) 2.0 के तहत की गई है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को संकट की घड़ी में अलग–अलग नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्त करना और उन्हें तेजी से सहायता उपलब्ध कराना है।सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में पुलिस (100), अग्निशमन सेवा (101), एंबुलेंसध्स्वास्थ्य सेवा (108), महिला सहायता (181), बाल सहायता (1098), गैस रिसाव (1906), बिजली आपूर्ति (19123), जल आपूर्ति (1916), दिल्ली मेट्रो (155370), और आपदा प्रबंधनध्राहत सेवाओं (1077) सहित कई आपात सेवाओं के लिए अलग–अलग हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी वजह से संकट की स्थिति में आम नागरिकों को भ्रम और देरी का सामना करना पड़ता है। ईआरएसएस 2.0 के तहत हर तरह की आपात स्थितियों में अब अलग–अलग नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। केवल 112 पर कॉल करके हर तरह की मदद मांगी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 112 को राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली भी इसे लागू करने का काम करने जा रही है। उन्होंने बताया कि ईआरएसएस 2.0 एक आधुनिक यूनिफाइड सिग्नल हैंडलिंग सिस्टम है, जिसमें सभी इमरजेंसी कॉल, मोबाइल ऐप इमरजेंसी, पैनिक बटन, एसएमएस और वेब अलर्ट एक ही पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट (पीएसएपी) पर प्राप्त होंगे। यहां से जिस भी तरह की इमरजेंसी होगी उसके आधार पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन सेवाओं को एक साथ अलर्ट किया जा सकेगा।

समय हर सवाल का जवाब देगा : डी.के. शिवकुमार

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान और अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि "समय हर सवाल का जवाब देगा।उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और मैं, दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में क्या चर्चा हुई और कौन–से फैसले लिए गए।सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने अपनी दिल्ली यात्रा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों को लेकर उठ रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मीडिया इसे ऐसे दिखाता है जैसे मैं दिल्ली सिर्फ राजनीतिक कारणों से या सरकार को अस्थिर करने के लिए जाता हूं। यह भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि राहुल गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वहीं, मीडिया में मेरे राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई गईं।"उन्होंने कहा, "मैं चुप रहना ही बेहतर समझता हूं और इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। एक बात तय है– समय हर बात का जवाब देगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।" अपने भाई और पूर्व कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश के उस बयान पर कि उन्हें हाईकमान से 'अच्छी खबर' मिलेगी, शिवकुमार ने कहा, "मेरे भाई, पार्टी कार्यकर्ता और यहां तक कि मीडिया भी यही कह रहा है कि मुझे अच्छी खबर मिलेगी। मेरे पास 140 विधायकों का समर्थन है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और मैं आपस में कैसे बात करते हैं? राहुल गांधी के सामने क्या चर्चा हुई और राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में क्या फैसले लिए गए– यह हम दोनों जानते हैं।अप्रैल में 'अच्छी खबर' मिलने के सवाल पर शिवकुमार ने कहा, "देखते हैं। अभी इस पर बात करने की क्या जरूरत है?" इस दौरान जेल में बंद अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता और डीजीपी के. रामचंद्र राव से जुड़े कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और मीडिया को इस संबंध में गृह मंत्री से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। शिवकुमार के नेतृत्व को लेकर दिए गए इन बयानों से राज्य की राजनीति और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर नई चर्चाओं और विवादों के तेज होने की संभावना है।

मायावती ने संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्रों के घटते समय और हंगामे पर जताई चिंता

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्रों के लगातार घटते समय, बार–बार होने वाले हंगामे और स्थगन को लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों की कार्यवाही के घटते समय पर व्यक्त की गई चिंता पूरी तरह उचित, सामयिक और सराहनीय है, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों को अति–गंभीर होकर ठोस अमल करना चाहिए। बसपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्देश में संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्र के घटते समय के साथ–साथ हर बार इनके भारी हंगामेदार एवं स्थगन आदि से इनकी जन उपयोगिता का घटता प्रभाव अक्सर गंभीर चिंता का विषय रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों चल रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के तीन–दिवसीय सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों की कार्यवाही के लगातार घटते समय पर चिंता व्यक्त किया जाना उचित, सामयिक व सराहनीय, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों को अति–गंभीर होकर इस पर अमल भी जरूर करना चाहिए। भारतीय संसद व राज्यों के विधानमंडल यहां देश की संवैधानिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था के अहम स्तंभ हैं तथा सरकार कार्यपालिका को देश व जनहित के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम हैं।

77वें गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे 10,000 मेहमान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इस साल 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड को देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में आय और रोजगार सृजन में अनुकरणीय कार्य करने वाले, सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और प्रमुख सरकारी पहलों के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मानित करने और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित किया गया है। इन विशेष अतिथियों को कर्तव्य पथ पर प्रमुख स्थान पर बैठाया जाएगा। समारोहों के अतिरिक्त, विशेष अतिथियों के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थानों के भ्रमण की व्यवस्था की गई है। उन्हें संबंधित मंत्रियों से बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। इस बीच, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त कई आतंकी खतरों की सूचनाओं के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे नई दिल्ली जिले में एक व्यापक, प्रौद्योगिकी–आधारित सुरक्षा तंत्र स्थापित किया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बैठने की जगहों का नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया है। मेहमानों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैनाती के तरीके में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने सभी आमंत्रित मेहमानों और टिकट धारकों से अपील की है कि वे अपने निमंत्रण कार्ड पर दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित मार्गों का ही पालन करें। मार्गों, पार्किंग और निर्धारित स्थानों से संबंधित पूरी जानकारी रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

अकाली दल और भाजपा ने पंजाब को लूटा – भगवंत मान

अमृतसर, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र अजनाला में आज 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सरकारी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने दशकों तक आपसी मिलीभगत से पंजाब की अंधाधुंध लूट की, राज्य की संस्थाओं को खोखला किया और युवाओं को रोजगार की तलाश में विदेश जाने के लिए मजबूर किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कॉलेज आम आदमी पार्टी की सरकार की शिक्षा को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और जनभागीदारी के माध्यम से पंजाब को फिर से "रंगला पंजाब" बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने घोषणा की कि इस कॉलेज का नाम सम्मानित शख्सियत बाबा गमचुक्क जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां राज्य सरकार हर संभव सुविधा और संस्थागत सहयोग प्रदान करेगी, वहीं हर पंजाबी का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे, ताकि पंजाब को फिर से "रंगला पंजाब" बनाया जा सके और हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े।इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पारंपरिक पार्टियों के भीतर आपसी कलह चरम पर है, क्योंकि इनके पास जनता के कल्याण के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा, "विपक्ष के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वे केवल जनता और राज्य के संसाधनों को लूटने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब के लोग समझदार और बहादुर हैं तथा ऐसे नेताओं के संदिग्ध चरित्र को भली–भांति पहचानते हैं।मुख्यमंत्री ने जनता से अवसरवादी और सत्ता–लोलुप नेताओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि पारंपरिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य पंजाब और इसके लोगों को लूटना रहा है। उन्होंने कहा"समय की मांग है कि ऐसी पार्टियों को पूरी तरह नकारा जाए, ताकि रंगला पंजाब बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें।" मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नए आम आदमी क्लीनिक विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

संपादकीय

ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराना ही बेहतर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को एक ऐसा प्रस्ताव मिला है, जिसे सरकार को फौरन नकार देना चाहिए। क्योंकि इसमें न केवल भारत की संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता पर खतरा खड़ा होगा, बल्कि घोर वैश्विक असंतुलन भी खड़ा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप गजा में शांति बहाल करने और स्थायी व्यवस्था निर्मित करने के लिए बनाए गए बोर्ड में भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण आया है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा कि भारत की भागीदारी से मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक श्ऐतिहासिक और निर्णायक प्रयासश को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे 7 अक्टूबर 2023 से जारी गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक नए और साहसिक वैश्विक दृष्टिकोण के रूप में पेश किया है। ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने 29 सितंबर, 2025 को गजा संकट को खत्म करने के लिए 20–बिंदुओं वाली योजना की घोषणा की थी, जिसे अरब देशों, इजरायल और यूरोप सहित कई वैश्विक नेताओं का समर्थन मिला था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे अनुमोदित किया था।लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। असल में यह बोर्ड ऑफ पीस पूरी वैश्विक व्यवस्था को उलट–पुलट करने के इरादे से बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इसके आजीवन अध्यक्ष रहेंगे, और वो हटते हैं तो उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। यानी अमेरिका अपनी चौधराहट अब नए तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा बोर्ड के जरिए केवल गजा तक नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के देशों की कमान संभालने का इरादा दिख रहा है।ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में जब गजा के लिए एक 20–सूत्रीय शांति योजना प्रस्तावित की थी तो इसमें गजा को एक श्अस्थायी शासनश के अधीन रखा जाना था, जिसका प्रबंधन एक श्तकनीकी, गैर–राजनीतिक फिलिस्तीनी समितिश द्वारा किया जाता। जब संरा ने इस बोर्ड को मंजूरी दी, तो इसका कार्यकाल 2027 के अंत तक सीमित था और फोकस केवल गजा पर था। लेकिन बोर्ड का चार्टर अब विस्तारित हो चुका है। अब यह सिर्फ मध्यपूर्व की शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि श्वैश्विक संघर्षों को सुलझानेश वाला एक श्नया अंतरराष्ट्रीय संगठन और अस्थायी शासन प्रशासनश के रूप में परिभाषित है। चार्टर में श्और संस्थाओं से अलग होने का साहसश पर जोर दिया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को खत्म कर, एक समानांतर व्यवस्था बनाने की चालाकी ट्रंप ने दिखाई है। बोर्ड का चार्टर श्संघर्ष से प्रभावितश या श्संघर्ष की धमकी वालेश क्षेत्रों में श्स्थायी शांतिश पर फोकस करता है। जहां श्धमकी वालेश क्षेत्र की परिभाषा साफ नहीं है। वैसे भारत इस व्यवस्था से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि चार्टर में लिखे श्संघर्ष की धमकी वाले क्षेत्रश जैसे अस्पष्ट शब्द भविष्य में कश्मीर जैसे मुद्दे पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे सकते हैं। ट्रंप अभी पहलगाम के बाद ही किस तरह दखलंदाजी करने लगे हैं, ये सबने देखा है। भारत की हामी के बाद तो उन्हें कश्मीर पर बोलने का लाइसेंस ही मिल जाएगा।दरअसल गजा को कट्टरता और आतंकवाद से मुक्त क्षेत्र बनाने, सुरक्षा ढांचा तैयार करने और पुनर्निर्माण करने के नाम पर ट्रंप अब एशिया और अफ्रीका के कमजोर देशों पर अमेरिकी पूंजीवाद के चंगुल और कसना चाहते हैं। नए निर्माण और सुरक्षा के नाम पर कमजोर देशों को मनमानी शर्तों पर समझौता करने मजबूर किया जाएगा और उससे बाद उनकी जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल ट्रंप अपने मुनाफे के लिए करेंगे। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे शांति बहाली या युद्ध रुकवाने में प्रभावी रहे न रहे, वहां सभी सदस्य देशों के वोट का महत्व है और वीटो शक्ति के कारण किसी एक देश की मनमानी नहीं चल पाती है। ट्रंप इसे खत्म करके एक नये किस्म की तानाशाही कायम करने की राह पर हैं और इसमें वो भारत को भी शामिल करना चाहते हैं।अब यह नरेन्द्र मोदी को तय करना है कि वे ट्रंप की मीठी–मीठी बातों में आते हैं या भारत के घरेलू और वैश्विक हितों पर दूरगामी नजरिया रखते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप का निमंत्रण ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ एक व्यापार समझौते पर काम कर रही है, ताकि भारतीय निर्यात पर लगे 50प्रतिशत शुल्क को कम किया जा सके। ट्रंप ने पहले ही भारत को परोक्ष रूप से धमका कर अपने फायदे के सौदे करवाए हैं। चाहे रूस से तेल खरीद कम करना हो या ईरान में चाबहार पोर्ट पर समझौते से पीछे हटना हो, मोदी सारे काम ट्रंप की सुविधा के लिए कर रहे हैं।

पतंगबाजी में मगन सरकार

असम के कालियाबोर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पर एक बेहूदा टिप्पणी की। इन चुनावों में भाजपा ने कई निगमों पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ी जीत तो बृहन्नमुंबई नगरपालिका में मिली है, जहां भाजपा ने शिवसेना को पीछे कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस को चौथा स्थान मिला है, जिस पर अपनी जीत का घमंड दिखाते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का जन्म 1885 में मुंबई में हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण पहले स्थान पर नहीं आ पाई। कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है क्योंकि उसके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है।असम चुनावों में महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनावों का जिक्र कर और उसमें भी कांग्रेस की हार पर टिप्पणी कर प्रधानमंत्री मोदी क्या हासिल करना चाहते हैं, यह समझना कठिन नहीं है। दरअसल उनकी सबसे बड़ी कुंठा ही यही है कि वे कांग्रेस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नेहरूजी से लेकर राहुल गांधी तक के लिए तमाम अपमानजनक और अक्सर झूठी बातें कहने के बावजूद गांधी परिवार को धर्मनिरपेक्ष राजनीति से डिगा पाने में नरेन्द्र मोदी असफल रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनावी जीत के बावजूद खुशी नहीं मिल पा रही।यूं भी नरेन्द्र मोदी चुनाव दर चुनाव जीतने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को कहां पूरा कर पा रहे हैं, उनकी जगह राहुल गांधी ही पीड़ितों के आंसू पोंछते नजर आते हैं। अभी इंदौर में ही कम से कम 24 लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हो गई। इसमें लोगों की नहीं सरकार की गलती है, जो लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पाई। अब भी कई लोग इसी वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन भाजपा अपनी गलती मानने की जगह मामले को किस तरह दबाने में लगी है, इसकी कई खबरें बाहर आ चुकी हैं।मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और इंदौर नगरनिगम पर भी भाजपा का ही कब्जा है। और इसके लिए भी भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी को ही श्रेय देते हैं। जैसे रविवार के कई अखबारों में मुंबई में जीत का श्रेय नरेन्द्र मोदी को देने वाले विज्ञापन एकनाथ शिंदे ने छपवाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी मोदी के नेतृत्व को ही जीत का श्रेय दिया है। लेकिन क्या मोदी की भूमिका यहीं तक सीमित है कि वे भाजपा को किसी भी तरह से जीत दिलाएं और उसके बाद हारे हुए दलों पर नकारात्मक टिप्पणी करें। क्यों नरेन्द्र मोदी को अब तक फुर्सत नहीं मिली कि वे एक बार कुछ घंटों के लिए ही इंदौर चले जाते। वहां भी राहुल गांधी ही पहुंचे।बता दें कि राहुल गांधी के इंदौर आने पर भी भाजपा विरोध कर रही थी। उसके मुताबिक राहुल गांधी राजनीति के मकसद से आ रहे थे। हालांकि इसे भाजपा की नासमझी ही माना जाए, क्योंकि राजनेता अगर राजनीति न करे तो फिर क्या करे। और अगर पीड़ितों के हक में आवाज उठाना या उनके आंसू पोंछने आना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति देश के हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए।

ममता बनर्जी को केंद्र सरकार से टकराने का बहाना चाहिए

योगेंद्र योगी

पश्चिम बंगाल देश के लिए ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इससे होने वाले राष्टघ्व्यापी नुकसान की ममता बनर्जी सरकार को परवाह नहीं है। ममता बनर्जी का तौरकृतरीका ऐसा बन चुका है मानो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होकर एक स्वतंत्र देश हो। ममता किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराती रही हैं। एक भी मौका केंद्र से टकराव का नहीं छोड़ती है और फिर खुद ही लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर सिर पर आसमान उठा लेती है। नया मामला प्रवर्तन निदेशालय के छापे की कार्रवाई का है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट पहुंच गई। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा– गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आई–पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी चुनाव से पहले उनकी पाटी तृणमूल कांग्रेस के संवेदनशील दस्तावेज जब्त कर राजनीतिक प्रतिशोध कर रही है। पुलिस ने ममता बनर्जी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू कर दी। यह मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट तक गया। कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेड मामले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। एजेंसी का कहना था कि पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज कर दी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता के तहत 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने ईडी की रेड में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा–धमकाकर सबूतों से छेड़छाड़ की। ममता सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला चुनावों के बीच उठाया गया है और इससे राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। ईडी चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल किया, "क्या लॉर्डशिप को लगता है कि हाईकोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, "कृपया हमारे मुंह में शब्द न डालें। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को "गंभीर" करार दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। हम इस पर परीक्षण करेंगे। अदालत ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से टकराने की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसका नमूना कोरोना महामारी में केंद्र के साथ टकराव, अम्फन तूफान को लेकर गृह मंत्री के साथ झगड़ा शामिल है। इस क्रम में बंगाली प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव को कौन भूल सकता है। बंगाल की सीमा पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आने वाले ट्रकों को लेकर भी केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव हुआ था। हुगली के तेलिनीपाड़ा में हुए दंगे को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ हुई रिपोर्ट पर राज्य पुलिस ने सांसद अर्जुन सिंह और लॉकेट बनर्जी समेत कई नेताओं पर मामले दर्ज कर एक और टकराव को जन्म दिया था। टकराव की इस कड़ी में नया मामला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का है।राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। यूपीएससी ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट को वापस लौटा दिया। यूपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश को तकनीकी और कानूनी आधार पर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे थे। लेकिन आयोग ने इस लिस्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। यूपीएससी का कहना है कि पुरानी प्रक्रियाओं में कई खामियां छोड़ी गई थीं। इसके चलते वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को सही नहीं माना जा सकता है। नियमों के मुताबिक सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर यह लिस्ट भेजनी चाहिए थी। यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अब यह मामला कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। सरकार के सामने अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगवानी तक के लिए नहीं आई और ना ही बैठक में शामिल हुई। पीएम का दौरा तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करना था। ओडिशा और बंगाल का दौरा तय हो जाने के बाद, दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ ही समय बताया गया था। लेकिन ओडिशा ने उस कार्यक्रम के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जबकि वो पीएम के बंगाल के दौरे से पहले था। ममता बनर्जी का आरोप था कि उन्हें पीएम मोदी का इंतजार करना पड़ा। जबकि पीएम को ही ममता का इंतजार करना पड़ा। पीएम के इंतजार करने की बात तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के ट्वीट से भी पुख्ता हुई थी। ममता बनर्जी अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर बैठक की जगह पहुंची जो कि हेलीपैड से सिर्फ 500 मीटर दूर था। पीएम से मिलकर वो 14.35 पर वापस भी चली गयीं। इसलिए वो सिर्फ 500 मीटर चलीं और 25 मिनट में वापस चली गईं। उनका पहले वापस जाना भी प्रोटोकॉल के खिलाफ था। इसलिए बंगाल सरकार का ये दावा गलत है कि ममता ने इंतजार किया बल्कि इसके उलट पीएम को ही इंतजार करना पड़ा था। केंद्र के साथ ममता के टकराव में बड़ा पेंच शारदा चिटफंड घोटाले ने भी बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची थी और उसे राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले सीबीआई अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के घर घुसने नहीं दिया गया।

टैरिफ के बावजूद वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊचाइयां

प्रह्लाद

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत के आर्थिक विकास से सबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए है। इस अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026–27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024–25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना हैय (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना हैय (3) सकल मान योग (ळतवै टंसनम ।ककपजपवद) में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान हैय (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई हैय (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमशरू 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई हैय (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णतरू नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं – स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में "देश प्रथम" के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धत्ता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें। किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दियारू आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी करना कदापि नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है।

जनतंत्र की खोखल, तानाशाह की जीत!

राजेंद्र

चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की अपनी चदरिया जिस तरह से उतार कर रख दी है और जिस तरह आयोग वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के शिविर का हिस्सा बन गया है, उसके बाद तो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले और उसके बाद के दौर में, व्यावहारिक मायनों में शायद ही कोई अंतर रह गया है। और चूंकि मोदी–शाह की जोड़ी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, उसके लिए तो यह विभाजन और भी आभासी है। फिर भी बाकायदा चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर मतदान तक के दौर और उससे पहले के दौर में, एक अवधारणात्मक अंतर तो अब भी बचा ही है।नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आने वाले विधानसभाई चुनावों के लिए अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। यह दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का एलान तक नहीं किया है। अनुमान है कि अप्रैल में होने वाले चुनावों के लिए, फरवरी के दूसरे पखवाड़े में चुनाव आयोग किसी समय चुनाव की तरीखों की घोषणा कर सकता है। यानी यह वह अंतराल है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी को आधिकारिक रूप से सत्ता के चुनावी दुरुपयोग से अपने चुनावी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए खुली छूट मिली रहती है। वैसे याद रखने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार उर्फ सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखकर, चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों का एलान करने बाद, विधिवत चुनाव प्रचार का जो दौर शुरू होता है, उसमें भी कौन सा सत्ताधारी पार्टी और उसके स्टार प्रचारकों को, किस तरह की रोक–टोक का सामना करना पड़ता है।चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की अपनी चदरिया जिस तरह से उतार कर रख दी है और जिस तरह आयोग वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के शिविर का हिस्सा बन गया है, उसके बाद तो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले और उसके बाद के दौर में, व्यावहारिक मायनों में शायद ही कोई अंतर रह गया है। और चूंकि मोदी–शाह की जोड़ी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, उसके लिए तो यह विभाजन और भी आभासी है। फिर भी बाकायदा चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर मतदान तक के दौर और उससे पहले के दौर में, एक अवधारणात्मक अंतर तो अब भी बचा ही है। लेकिन, हमेशा से ऐसा ही नहीं था। बेशक, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और आम तौर न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक, राज्य के स्वतंत्र स्तंभों से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं तक पर, कार्यपालिका की ताकत के बल पर, तमाम वैध–अवैध तरीकों से तेजी से कब्जा कर लिया गया है। लेकिन, इससे पहले तक हमारी चुनाव व्यवस्था के विकास की दिशा इससे ठीक उल्टी थी। बेशक, चुनाव प्रणाली पूरी तरह से दोषमुक्त तो शायद कभी भी नहीं थी, फिर भी उसके विकास की दिशा चुनावों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी बनाने की ओर थी। यहां तक कि पिछली सदी के आखिरी दशक में तो टीएन शेषन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने के लिए मजबूत शुरूआतें भी की थीं, जिनमें आदर्श चुनाव संहिता का लागू किया जाना भी शामिल था। और इसके लिए उन्होंने लड़कर कार्यपालिका से चुनाव आयोग की निष्पक्षता हासिल की थी, जो कि चुनाव प्रक्रिया की तमाम निष्पक्षता की बुनियाद है।लेकिन, अब चुनाव प्रक्रिया के विकास की उस दिशा को पूरी तरह से ही पलटा जा चुका है। उल्टे चुनाव प्रक्रिया पर पूरी तरह से कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित कराया जा चुका है। और इस उल्टी यात्रा में स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जनतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के आश्वासनों को अधिक से अधिक खोखला करने के लिए, नित नये–नये तजुर्बे किए जा रहे हैं। एसआइआर या मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण, ऐसा ही ताजातरीन एक्सपेरीमेंट है, जिसने चुनाव प्रक्रिया को जनता की राय जानने की प्रक्रिया के बजाए, शासन के मर्जी से मतदाताओं के ही छांटे जाने की प्रक्रिया बनाए जाने का खतरा पैदा कर दिया है।यह खतरा कितना वास्तविक है, इसका अंदाजा जिन राज्यों में इस समय यह प्रक्रिया चल रही है, वहां इस प्रक्रिया को मतदाताओं की टार्गेटेड छंटनी का हथियार बनाए जाने की हर रोज आ रही खबरों से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और दलित तथा अन्य कमजोर जातियों व महिलाओं के नाम काटे जाने की खबरें आने के साथ–साथ, मुस्लिम बस्तियों में रहने वालों के पतों पर, बड़ी संख्या में अनजाने हिंदुओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जाने की खबरें आ रही हैं। उधर राजस्थान से एक हिंदू मतदाता सूची अधिकारी का वीडियो संदेश सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है जिसमें यह अधिकारी इसकी धमकी दे रहा है कि अगर उस पर मुसलमानों के नाम काटने और दबाव डाला गया तो, वह आत्महत्या कर लेगा।और पश्चिम बंगाल में तो, जहां मतदाता सूची के काम में लगे अधिकारियों की चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में आत्महत्याओं ने इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा ही बना दिया है, भाजपा नेताओं की गाड़ियों में हजारों की संख्या में, मतदाताओं के नाम काटे जाने के प्रपत्र पकड़े गए हैं। यह लक्षित तबकों या संभावित रूप से विरोधी मतदाताओं के नाम कटवाने के संगठित खेल की कहानी कहता है। राजस्थान में भी, पहले चरण में नहीं काटे जा सके, राजनीतिक विरोधी व अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए, डेढ़ लाख से ज्यादा परिपत्र मशीनों की मदद से जमा कराए जाने के उदाहरण सामने आये हैं। पाठकों को याद दिला दें कि संगठित तरीके से और औद्योगिक पैमाने पर, वर्तमान मतदाताओं के नाम कटवाने का यह खेल सबसे पहले राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पकड़ा गया था, जिसे भाजपा–विरोधी पार्टियों के हो–हल्ला करने के बावजूद, चुनाव आयोग ने बहुत हद तक अनदेखा ही कर दिया था।

टीबी के नोडल डीआर सेंटर पर दो साल में नहीं भर्ती हुआ एक भी मरीज

लखनऊ, (संवाददाता)। दवा प्रतिरोधी (डीआर) टीबी पर नियंत्रण के लिए की जा रहीं कोशिशें धरातल तक नहीं पहुंच रही हैं। डीआर टीबी के लिए नोडल सेंटर बनाए गए संजय गांधी पीजीआई में दो साल में एक भी मरीज भर्ती नहीं किया गया। यहां मरीजों को सिर्फ दवाएं दे दी जाती हैं। भर्ती की जरूरत होने पर उन्हें केजीएमयू या अन्य संस्थान रेफर कर दिया जाता है। टीबी की बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा प्रतिरोधी टीबी के नोडल सेंटर बनाने का निर्देश दिया था। इसके तहत दिसंबर 2023 में लखनऊ में केजीएमयू, लोहिया संस्थान और एसजीपीजीआई समेत प्रदेश में कुल 24 नोडल केंद्र बनाए गए। गाइडलाइन के अनुसार, सामान्य टीबी सेंटर को न्यूनतम चार और नोडल सेंटर को न्यूनतम 12 बेड पर मरीज भर्ती करने हैं। इसके बावजूद पीजीआई ने एक भी मरीज भर्ती नहीं किया। 22 वर्षीय युवती (मरीज संख्या– 2025315978) को वर्ष 2025 में संजय गांधी पीजीआई में हुई जांच में दवा प्रतिरोधी टीबी की पुष्टि हुई। हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती करने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें केजीएमयू भेज दिया गया। केजीएमयू में युवती का उपचार चल रहा है। 26 वर्षीय युवक (मरीज संख्या– 2025290385) ने सांस संबंधी समस्या होने पर पीजीआई में दिखाया। जांच में उन्हें कई दवाओं से प्रतिरोधी टीबी की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें केजीएमयू भेज दिया गया। 75 वर्षीय बुजुर्ग (मरीज संख्या– 2025290385) क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) की समस्या के साथ 18 जून 2025 को भर्ती हुए थे। इलाज के दौरान उन्हें कई दवाओं से प्रतिरोधी टीबी की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वह केजीएमयू से इलाज करा रहे हैं। पीजीआई को नोडल सेंटर बनाए जाने के बाद माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विशेष लैब बनाने के लिए करीब एक करोड़ रुपये का बजट मिला। इस लैब से सामान्य के साथ दवा प्रतिरोधी टीबी की जांच की सुविधा शुरू हो गई। लैब शुरू होने के बाद टीबी की जांच तो हो रही है, लेकिन गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के हर अंग में इसका संक्रमण हो सकता है। टीबी के इलाज के लिए आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पाइराजिनामाइड, एथमब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राथमिक पहली पंक्ति की दवाएं हैं। अगर किसी मरीज में इनमें से रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड समेत कोई दवा काम नहीं करती है तो उसे दवा प्रतिरोधक टीबी कहा जाता है। ऐसे में अगली पंक्ति की दवाएं चलानी पड़ती हैं। यह स्थिति सामान्य के मुकाबले रोग के गंभीर होने की निशानी है। प्संस्थान को नोडल सेंटर बनाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक मरीज भर्ती करने के लिए कोई बजट नहीं मिला है। संस्थान में इसके लिए अलग से वार्ड बनाना होगा, क्योंकि टीबी मरीजों को केंद्रीकृत वातानुकूलित कक्ष में नहीं रखा जा सकता। प्संस्थान में स्थित डाट्स सेंटर के माध्यम से टीबी के रोगियों को दवाएं दी जा रही हैं। मरीजों का इलाज पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में किया जाता है। भर्ती संबंधी व्यवस्था पल्मोनरी मेडिसिन विभाग ही देखता है।

समर्थकों संग अस्पताल पहुंचकर सपा विधायक ने किया हंगामा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर विस्तार स्थित इकाना मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में मरीज की मौत के बाद शव न देने पर रविवार रात सपा विधायक ने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। आरोप है कि स्टाफ से अभद्रता भी की। अस्पताल

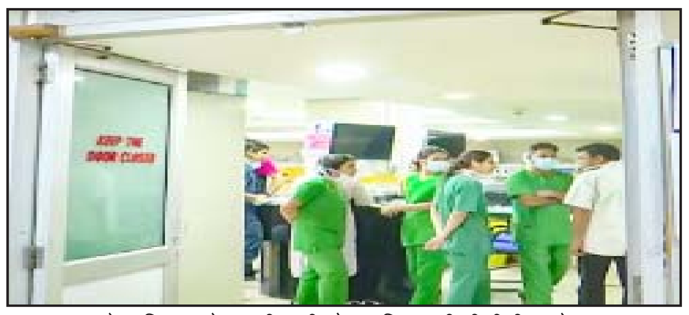

संचालक ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। 55 वर्षीय अरबाज गोमतीनगर विस्तार स्थित इकाना मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती थे। आंत फटी होने के साथ उन्हें कई अन्य गंभीर समस्याएं थीं। वह करीब 25 दिन से वेंटिलेटर पर थे। रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बकाया तीन लाख रुपये अदा कर शव ले जाने के लिए कहा। रविवार रात करीब 9 बजे सपा विधायक अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए और शव रोकने का आरोप लगाकर हंगामा किया। इसके बाद बकाया बिल भुगतान किए ही शव लेकर चले गए।

संक्षिप्त खबरें

एलयू में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा जल्द कराने का आश्वासन

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के बीएससी (गणित व जूलॉजी) के जिन विद्यार्थियों के बैक पेपर छूट गए थे, उन्होंने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने कुलपति प्रो. जेपी सैनी और परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) से जुड़े विद्यार्थियों ने मांग की कि जिन छात्रों के बैक पेपर छूट गए हैं, उनकी परीक्षा शीघ्र कराई जाए, ताकि किसी का भी शैक्षणिक सत्र बर्बाद न हो। एनएसयूआई के सदस्य प्रिंस प्रकाश, अंकुश चौहान, अरसलान और अमित ने बताया कि वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बीएससी (गणित व जूलॉजी) के छूटे हुए बैक पेपर की परीक्षा जल्द कराने का आश्वासन दिया गया है।

पॉडकास्ट व बेहतर कंटेंट में भी बना सकते हैं कॅरिअर : डॉ. मुकुल

लखनऊ, (संवाददाता)। इंटरनेट के दौर में आज पॉडकास्ट एक बेहतर विकल्प है। कंटेंट आपका अच्छा है तो इंटरनेट की दुनिया में कॅरिअर बनाया जा सकता है। ये बात लखनऊ विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के प्रोफेसर डॉ. मुकुल श्रीवास्तव ने कहीं। मौका था सोमवार को नेशनल पीजी कॉलेज में छह दिवसीय साउंड क्रॉफ्ट द ऑडियो वर्कशॉप के पहले दिन का। उन्होंने कहा कि रेडियो में ये जरूरी नहीं है कि क्या बोला जा रहा है बल्कि ये जरूरी है कि कैसे बोला जा रहा है। आज इंटरनेट पर सब कंटेंट क्रिएटर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन श्रोता कौन बनेगा ये आपका बेहतर कंटेंट ही तय करेगा। कंटेंट की दुनिया बहुत क्रूर होती है। लोगों को बहुत जल्दी भुला देती है। उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। बताया कि रेडियो की दुनिया में प्रोमो लिखना और गढ़ना दोनों होता है। रेडियो और ऑडियो के लिए काम करने के लिए पहले से तैयारी करनी होती है। उच्चारण, शब्द ज्ञान और विषय ज्ञान जरूरी है। इस मौके पर प्राचार्य देवेंद्र सिंह सहित शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के मदरसे को खोलने का दिया आदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती के बगैर मान्यताप्राप्त मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की 24 घंटे में सील खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मदरसे को बंद करने के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 1 मई 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मान्यता न होने के कारण किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। कहा कि बिना मान्यता मदरसा केवल सरकारी अनुदान का हकदार नहीं होगा और उसके छात्रों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के कई गैर–मान्यता प्राप्त मदरसों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह फैसला इस मदरसे के प्रबंधक की याचिका मंजूर करके दिया।

यूपी में बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाई एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत शोध, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और इससे जुड़े स्टार्टअप्स को पांच वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को कम कर उत्तर प्रदेश को देश की ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाना है। योजना के अनुसार, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ये सेंटर देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से संचालित होंगे। यहां होने वाला शोध उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जिससे व्यावहारिक और किफायती समाधान विकसित किए जा सकें। राज्य सरकार इन दोनों सेंटरों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस राशि से अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, परीक्षण सुविधाएं और हाई–एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में गोरखपुर में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा चुका है, जिससे अनुमानतः 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा प्रदेश में कई ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के इनक्यूबेटर से जुड़े स्टार्टअप्स को पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये की ।

सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ा है, जिसे बेनकाब करना जरूरी : राहुल गांधी

लखनऊ, (संवाददाता)। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भुएमऊ गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लड़ते रहना है और डरना नहीं है। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार धर्म का आडंबर ओढ़े हुए है, जिसे बेनकाब करना आवश्यक है। बैठक में आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के चयन और पार्टी की रणनीति पर गहन विचार–विमर्श किया गया। राहुल गांधी ने पार्टी की युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इस संकेत से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आगामी पंचायत चुनावों में युवा चेहरों पर भरोसा जता सकती है। पार्टी का मानना है कि युवा जोश और नए विचारों से संगठन को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा। इस अवसर पर, सांसद

राहुल गांधी ने 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और आठ नए कार्यों का शिलान्यास भी किया। इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बाद, उन्होंने रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। विकास कार्यों के उद्घाटन और खेल आयोजन के पश्चात, राहुल गांधी नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर के आवास पर पहुंचे। उन्होंने वहां पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में अहम माना जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

प्रदेश के 103 सर्वोदय विद्यालयों में 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में संचालित 103 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 2026–27 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होने की जानकारी दी है। इस प्रक्रिया के तहत कक्षा 6, 7, 8 और 9 की खाली सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 मार्च को जारी किए जाएंगे, जबकि परीक्षा 15 मार्च 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा के परिणाम 23 मार्च 2026 को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी और नए सत्र के लिए चयनित छात्रों को आवासीय सुविधाओं सहित शिक्षा प्रदान की जाएगी।उपनिदेशक जे राम ने बताया कि सर्वोदय विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी शिक्षा, खेल और विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इन 103 आवासीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ श्रम और छम्ज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी छात्रों के समग्र विकास के लिए संचालित किए जा रहे हैं।प्रवेश के लिए पात्रता भी स्पष्ट की गई है। केवल वही अभ्यर्थी प्रवेश के लिए योग्य होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक न हो।

यूपी दिवस–2026 पर दिल्ली हाट में सजेगी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक संध्या

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2026 की शाम 05:30 बजे से राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तर प्रदेशवासी, 18 से 20 देशों के राजनयिक, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश से जुड़े विशिष्टजनों की सहभागिता प्रस्तावित है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं और परंपराओं को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना है।जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी दिवस–2026 के अवसर पर दिल्ली हाट को 'विकसित उत्तर प्रदेश' की थीम पर विशेष रूप से सजाया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश की विविध नृत्य शैलियों और परंपराओं को दर्शाती मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी। इसके साथ ही पारंपरिक हस्तशिल्प की झलक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर अलग–अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि जिन देशों में उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है।

26 तक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस का जश्न

लखनऊ, (संवाददाता)। सामाजिक संस्था जश्न–ए–आजादी की ओर से गणतंत्र दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। यूपी प्रेस क्लब में हुई प्रेसवार्ता में संस्था की अध्यक्ष रजिया नवाज ने कहा कि इस बार भी सभी वर्गों और धर्मों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। संस्था के संस्थापक सदस्य मुर्तजा अली और बज्मी युनुस ने बताया कि 18 से 26 तक आयोजन होने हैं। 18 को काकोरी कांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 20 को निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, 21 को शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, 22 को सर्वोदय नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी को विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण, 24 को शहीदों एवं महापुरुषों की मूर्तियों की साफ–सफाई व माल्यार्पण और 25 को भारतीय संविधान पर संगोष्ठी होगी। 26 जनवरी को सुबह 11:05 बजे हजरतगंज स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के बाहर सभी धर्मों के धर्माचार्यों की उपस्थिति में ध्वजारोहण होगा। तिरंगे गुब्बारे और शांति के प्रतीक कबूतर आकाश में छोड़े जाएंगे। शाम को हजरतगंज व्यापार मंडल एवं जत्र–ए–आजादी के संयुक्त तत्वावधान में देशभक्ति से ओत–प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर वामिक खान, मुर्तजा अली, अब्दुल वहीद, कवि वेदव्रत वाजपेयी और मनुव्रत वाजपेयी भी मौजूद रहे।

पांडुलिपि कार्यशाला में संरक्षण और शोध पर जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरों और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में सरकार की पहल को अमली जामा पहनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। यहां राजकीय अभिलेखागार में सोमवार से शुरू हुई पांच दिवसीय अभिलेख एवं पांडुलिपि अभिरुचि कार्यशाला में इतिहास शोध के नए आयाम, डिजिटाइजेशन, अभिलेख संरक्षण और आर्काइव्स में कॅरिअर की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली डॉ. राजमणि ने प्राथमिक शोधार्थियों को सोशल मीडिया व इंटरनेट की सूचनाओं को बिना सत्यापन शोध में शामिल न करने की सलाह भी दी। आर्काइव्स का क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, निजी कंपनियां और विश्वविद्यालय भी अपने अभिलेखागार विकसित कर रहे हैं। निदेशक अभिलेखागार अमित कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि 700 से अधिक पंजीकरण में से 200 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत 75 जिलों में पांडुलिपियों का सर्वे व डिजिटाइजेशन होगा। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में विशिष्ट अतिथि निदेशक, हिस्ट्री डिवीजन, रक्षा मंत्रालय डॉ. अमलेश कुमार मिश्र ने सैन्य अलंकरणों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित वीरों के योगदान की चर्चा की। वर्ष 1950 में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत हुई। अब तक 21 परमवीर चक्र, 214 महावीर चक्र और 1300 से अधिक वीर चक्र दिए जा चुके हैं।

आधी आबादी सबसे अधिक प्रभावित, 30 फीसदी से अधिक घटी संख्या

लखनऊ, (संवाददाता)। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिले में जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। प्रक्रिया के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में 56,972 महिला मतदाताओं की संख्या घट गई है। जिले में पहले 18,80,029 महिला मतदाता थीं, अब 13,10,237 रह गई हैं। इस तरह जिले में करीब 30.31 फीसदी महिला मतदाताओं की संख्या घट गई है। आपत्ति के लिए अब इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। पहले जिले में एसआईआर प्रक्रिया से पहले जिले में 21,14,356 पुरुष मतदाता थे, जो अब घटकर 14,84,071 रह गए। यानी 6,30,285 पुरुष मतदाता सूची से बाहर हो गए, जो कुल पुरुष मतदाताओं का करीब 29.81 प्रतिशत है। कुल मिलाकर जिले में मतदाताओं की संख्या एसआईआर के बाद 39,94,535 से घटकर 27,94,397 रह गई है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से राजनीतिक दलों के साथ–साथ सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित और दोहरे नामों को हटाकर सूची को शुद्ध करना है। विभाग के मुताबिक, जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, वे सुधार अभियानों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म छह (नया मतदाता बनने के लिए) भरते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार मान्य है, लेकिन उसके साथ आवेदक को घोषणा पत्र भरना होगा। अगर घोषणा पत्र भरते समय आवेदक की मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से हो जाती है तो उसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, अगर सही मैपिंग नहीं होती है तो उसे नोटिस मिलेगा और उसे साक्ष्य देने होंगे। उन दस्तावेजों में आधार मान्य नहीं होगा।

व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर नोडल अधिकारियों से लिया जाएगा स्पष्टीकरण : धर्मपाल सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में प्रदेश के गौ आश्रय स्थलों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नोडल अधिकारियों द्वारा गोशालाओं के निरीक्षण के दौरान यदि व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। गोशालाओं के संचालन में अव्यवस्था, उदासीनता अथवा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक गौ आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हों और पराग के माध्यम से पौष्टिक पशु आहार की निर्बाध आपूर्ति की जाए। साथ ही गौशालाओं को गोद लेने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया।मंत्री ने कहा कि मंडल स्तरीय जनपदों की सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके। गोवंश के लिए दवाइयों एवं वैक्सीन का समुचित प्रबंध किया जाए। जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी नियमित रूप से गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें और चारा, भूसा, स्वच्छ पानी तथा प्रकाश व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए गोवंश के बचाव के लिए त्रिपाल, अलाव सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं, ताकि चारा, भूसा या दवाओं के अभाव में किसी भी गोवंश की मृत्यु न होने पाए। पशुचिकित्साधिकारी स्वयं गौ आश्रय स्थलों पर जाकर गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं औषधि व्यवस्था की निगरानी करें तथा हरे चारे एवं पशु आहार की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।अवस्थापना कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि इनके लिए बजट का यथाशीघ्र आवंटन कर समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाएं और कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। कार्यदायी संस्थाओं को ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। बैठक में 76 प्रतिशत बजट व्यय किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि शेष बजट भी शीघ्र योजनाओं के लिए अवमुक्त किया जाए और किसी भी मद का बजट सरेंडर न होने पाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में 7,497 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 12,38,447 निराश्रित गोवंश संरक्षित किए गए हैं।दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि दुग्ध समितियों की पुरानी क्रियान्वयन पद्धति की समीक्षा कर वर्तमान आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के अनुरूप ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। किसी भी स्थिति में पुरानी दुग्ध समितियां बंद न हों। जो नई समितियां गठित हो चुकी हैं, उनका विधिवत संचालन सुनिश्चित किया जाए और समितियों को समय पर भुगतान किया जाए। पराग के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ यह भी कहा गया कि उत्पादों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।बैठक में पशुधन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने मंत्री को विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए आश्वस्त किया कि प्राप्त दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निदेशक, पशुधन को निर्देशित किया कि मंडलवार प्रतिदिन गौशालाओं की स्थिति की गहन समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही गौ आश्रय स्थलों पर ठंड से बचाव सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था और अवस्थापना संबंधी कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पाण्डेय, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव, पशुपालन विभाग के निदेशक (प्रशासन एवं विकास) मेम पाल सिंह, निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक पी के सिंह सहित पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, की नैक तैयारी से संबंधित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन, लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की नैक तैयारी से संबंधित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा नैक के सभी 11 एट्रीब्यूट पर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से गहन समीक्षा की गई। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रश्नपत्र द्विभाषीय (हिंदी/अंग्रेजी) हों तथा क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराए जाएँ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से अधिक से अधिक फीडबैक लेकर उसे प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। सभी एट्रीब्यूट में गुणवत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक फोटोग्राफ्स उचित कैप्शन के साथ प्रदर्शित करने पर विशेष जोर दिया गया।राज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम, वॉर्ड, प्रयोगशालाओं में हो रहे प्रायोगिक कार्य, ऑडिटोरियम के उपयोग, दीक्षांत समारोह, आंगनवाड़ी एवं एच0पी0वी0 टीकाकरण, सम्मेलन, सेमिनार, विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों, लिफ्ट दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग करते हुए आदि के फोटोग्राफ्स प्रभावी कैप्शन के साथ प्रस्तुतीकरण में शामिल किए जाएँ। सभी गतिविधियों को फोटो के माध्यम से स्पष्ट रूप से दर्शाने के निर्देश दिए गए।राज्यपाल ने कुलपति को निर्देशित किया कि प्रत्येक एट्रीब्यूट की स्वयं समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें।संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय से अपनी-अपनी सूचनाओं की जाँच करें, छूटी हुई जानकारी का समावेश करें तथा अनावश्यक सामग्री को प्रस्तुतीकरण से हटाएँ।राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु किए गए एम0ओ0यू0 की पृथक सूची एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों, विशेषकर अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ विश्वविद्यालय की सहभागिता, बच्चों के लिए एच0पी0वी0 टीकाकरण एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे प्रयासों को प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित करने पर भी बल दिया गया।राज्यपाल ने निर्देश दिए कि नैक प्रत्यायन की तैयारी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए तथा सभी सूचनाओं को सुव्यवस्थित, तथ्यात्मक एवं गुणवत्ता-युक्त रूप में प्रस्तुत किया जाए।

25 जनवरी को मनाया जाएगा-16वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानन्द झा द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनपद स्तर व तहसील स्तर पर वृहद रुप से मनाये जाने हेतु चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 25 जनवरी को 16वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी तहसील स्तर व समस्त मतदेय स्थलों पर कार्यक्रम होगा और मतदाता शपथ दिलाई जायेगी तथा नये युवा मतदाता को ईपिक कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। मुख्य कार्यक्रम टी डी इन्टर कालेज में दिन में 11 बजे से आयोजित है। नगर के सभी इन्टर व डिग्री कालेज से छात्र छात्राएं अपने कालेज से मतदाता जागरूकता रैली लेकर बैनर के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल टी डी इन्टर कालेज पहुंचेगे, जहाँ पर मतदाता जागरूकता विषय पर रंगोली, मेहंदी व पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, तथा विजेताओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूर्ण मनोयोग एंवम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए। बैठक में प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी लाल बहादुर, सह जिला विद्यालय निरीक्षक विवेक सिंह, जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा, वरिष्ठ सहायक महमूद अली, शिवकुमार , डॉ ब्रहम प्रकाश प्रधानाचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

श्री बाबा जंगली नाथ महादेव धाम से धूमधाम से निकली शोभायात्रा यात्रा को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में लोगों ने दिखाया उत्साह

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। दावतपुर वलीपुर गांव में स्थित श्री बाबा जंगली नाथ महादेव धाम से बुधवार समय 11:00 से पूर्व रचित कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकल गई। जिसमें सैकड़ो की संख्या में महिलाओं ने बड़े ही उत्साह पूर्वक कलश यात्रा में शामिल हुई यात्रा श्री बाबा जंगली नाथ महादेव धाम से वलीपुर बाजार दावतपुर वलीपुर गांव असरगपुर पूरे सिधाई भगत पूरे जोधी होते हुए । आदि गंगा मां गोमती के तट मिटानेपुर घाट से माता व बहनों ने आदि गंगा मां गोमती से जल लेकर पुनः वापस बाबा जंगली नाथ महादेव धाम को प्रस्थान कर रहे हैं । यात्रा में महिलाओं के साथ-साथ पुरुष बहन भाइयों की भी काफी संख्या उत्साहवर्धन करते हुए कलश यात्रा को सफल बनाने में चार चांद लग रही है यात्रा में शामिल सूर्यपुत्र घोड़ा आगे आगे डीजे के धुन पर यात्रा में शामिल महिलाएं व पुरुष बहन भाई रखते हुए नजर आ रहे हैं ।

मैक्स अस्पताल, लखनऊ के डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की देर से पहचान को बताया गंभीर स्वास्थ्य समस्या

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। शहरी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की पहचान अब भी देर से हो रही है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर लखनऊ जैसे शहरों में यह एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में गायनेकोलॉजिकल ऑन्को-सर्जरी की कंसल्टेंट डॉ. चंद्रिमा रे ने बताया कि जानकारी की कमी, डर और गलतफहमियां देर से जांच की मुख्य वजह हैं। उन्होंने कहा, "अच्छे अस्पताल और जांच सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद कई महिलाएं नियमित स्क्रीनिंग से बचती हैं। पैप स्मीयर जांच को लेकर दर्द होने की गलत धारणा है, साथ ही मानसिक और आर्थिक बोझ का डर भी रहता है।"

किसान दिवस का आयोजन, पशुपालन एवं मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के निर्देश

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तवजौनपुर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं एवं कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी अपनाएं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों को निर्देशित किया कि मधुमक्खी पालन के संबंध में किसानों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। साथ ही मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधनों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि के साथ सहायक व्यवसायों को अपनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जिलाधिकारी के द्वारा किसानों को समन्वित खेती करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि उद्यान विभाग के द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि वी बी द्विवेदी, जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, डिप्टी पीडी आत्मा डॉ0 रमेश चंद्र यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।

एसएसपी डाक्टर गौरव ग्रौरव ने किया निरीक्षक व उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र मे फेरबदल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।बुधवार जिले में अपराध को चुस्त दुस्त बनाए रखने के लिए एसएसपी अयोध्या डॉ. गौरव ग्रोवर ने पुलिस विभाग में कई निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है।जिसमें कुमारगंज थानाध्यक्ष रहे ओमप्रकाश के इसी माह सेवा निवृत होने के चलते उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है।फेरबदल की कड़ी में निरीक्षक देवेंद्र पांडे को प्रभारी निरीक्षक थाना तारुन बनाया गया है।वहीं पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक संतोष कुमार को प्रभारी निरीक्षक थाना कुमारगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके अलावा निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव को पुलिस लाइन से प्रभारी मीडिया मॉनिटरिंग सेल/सोशल मीडिया सेल बनाया गया है।जबकि अपराध शाखा में तैनात निरीक्षक परशुराम ओझा को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा नियुक्त किया गया है।कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक विजय प्रताप तिवारी को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली बीकापुर बनाया गया है।थाना तारुन के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक संदीप कुमार त्रिपाठी को पुलिस लाइन (स्थानांतरणाधीन) किया गया है।एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर द्वारा किए गए इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।पुलिस विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

आजमगढ़ एयरपोर्ट सुपरजॉइंट्स ने ट्रॉफी पर किया कब्जा

गोरखपुर, (संवाददाता)। 02वीं वाहिनी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर की ओर से आयोजित अंतर्व्यवस्थापन क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें आजमगढ़ एयरपोर्ट सुपरजॉइंट्स ने कुशीनगर एयरपोर्ट राइनोज को छह विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में कुशीनगर एयरपोर्ट राइनोज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुशीनगर एयरपोर्ट राइनोज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में सभी विकेट खोकर 127 रन बनाए, जवाब में आजमगढ़ एयरपोर्ट सुपरजॉइंट्स के बल्लेबाज अजय वर्मा की 85 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को फाइनल मैच को छह विकेट से जीता दिया। शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच वाहिनी सुपर किंग्स और कुशीनगर एयरपोर्ट राइनोज के बीच खेला गया, जिसमें कुशीनगर एयरपोर्ट राइनोज की टीम ने वाहिनी सुपर किंग्स को चार विकेट से हराया। दूसरा सेमीफाइनल मैच आजमगढ़ एयरपोर्ट सुपरजॉइंट्स और गोरखपुर कोर्ट धुरंधर के बीच खेला गया। इसमें आजमगढ़ एयरपोर्ट सुपरजॉइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 144 रन बनाए, जवाब में गोरखपुर कोर्ट धुरंधर की टीम 10.5 ओवर में 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सेनानायक देवेंद्र भूषण ने विजेता टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर वाहिनी के सहायक सेनानायक सतीश चंद्र पांडेय, संजीव कुमार, अजय विक्रम सिंह, सत्यम यादव, सुधीर सिंह, रामदयाल सिंह आदि मौजूद रहे।

सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के हाथों ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांगजनों के खिले चेहरे

अयोध्या। दिव्यांग जनों के चेहरे पर उस समय खुशी की लहर साफ-साफ दिखाई दिया।जब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक बचपन डे केयर सेंटर परिसर जोगी तारा अयोध्या में सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा ट्राई साइकिल पाया।इस संबंध में जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने बताया मंगलवार को विधायक सदर वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा बचपन डे केयर सेंटर परिसर जोगीतारा अयोध्या में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन कर 36 ट्राईसाईकिल का वितरण किया गया।इस मौके पर सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दिव्यांग जन समाज का अभिन्न अंग है और उनकी सुविधा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना सरकार के प्राथमिकता है।ट्राईसाईकिल मिलने से दिव्यांग जनों को आवागमन में सुविधा होगी तथा वह दैनिक कार्य अधिक सहजता से कर सके।कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसका लाभ पात्र व्यक्तियों तक निरंतर पहुंचा जा रहा है।कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

2.5 करोड़ से 12 समितियों पर 100 टन क्षमता के बनेंगे गोदाम

भदोही, (संवाददाता)। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिले की 12 सहकारी समितियों में 100 टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनेंगे। गोदाम निर्माण के लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा। एआर सहकारिता राम प्रकाश ने बताया कि 12 समितियों पर गोदाम का प्रस्ताव बनाया गया है। जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर एस्टीमेट तैयार होगा। अनुमान जताया कि एक-एक गोदाम के निर्माण पर 20 लाख रुपये खर्च होंगे। 12 समितियों पर करीब ढाई करोड़ खर्च किया जाएगा। इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। जिले में 52 सहकारी समितियां हैं। इसमें 45 क्रियाशील हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से समितियों को समृद्ध बनाने की कवायद चल रही है। वी-पैक्स के माध्यम से समितियों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, हालांकि धान, गेहूं खरीद के सीजन में भवन की कमी के कारण भंडारण में दिक्कत होती है। दो से ढाई दशक पहले बने गोदाम जर्जर हो चुके हैं। इससे भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान न होने पर कई बार अनाज बारिश में भींग जाता है। इससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 12 सहकारी समितियों में गोदामों के निर्माण किए जाएंगे।

भाषण प्रतियोगिता में बुशरा प्रथम, वंदना को मिला दूसरा स्थान

भदोही, (संवाददाता)। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को सड़क सुरक्षा विषयक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा-चुनौतियां एवं सावधानियां विषय पर 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बुशरा प्रथम, वंदना राय द्वितीय और अनीशा तृतीय रहीं। प्रतिभागियों ने भाषण के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला। इसमें यातायात नियमों की अनदेखी, सुरक्षा उपाय न करने को मुख्य समस्या बताया। कई प्रतिभागियों ने अपने रचनात्मक सुझाव दिए। इस मौके पर प्राचार्या डॉ. माया ने सड़क सुरक्षा को सामाजिक दायित्व बताते हुए विद्यार्थियों से खुद यातायात नियमों का पालन करने और लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर डॉ. अंकिता तिवारी, डॉ. ऋतिक रंजन सिंह, डॉ. अनीश मिश्र, डॉ. अमित तिवारी, डॉ. अमर कृष्ण यादव रहे।

खनन विभाग ने पांच ट्रैक्टर-टॉली को किया सीज

भदोही, (संवाददाता)। मिट्टी के अवैध खनन एवं विनियमन शुल्क जमा नहीं करने पर खनन विभाग ने सोमवार को धसकरी और भिखारीपुर गांव में पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया। संचालकों को नोटिस जारी करके दो दिन में शुल्क जमा करने का अल्टीमेटम दिया। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह सोमवार को धसकरी गांव पहुंचे। जहां निर्देश के बाद भी विनियमन शुल्क जमा नहीं करने पर आरपीवाई और एमएलवाई ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस देते हुए एक-एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को कारपेट सिटी चौकी में सीज किया।

किसी के पिता बदल गए तो किसी के पति

उन्नाव, (संवाददाता)। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की 19,17,882 (पुरुष 1056458, महिला 861381 व थर्ड जेंडर 43) की अनंतिम मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हिंदू के घर में मुस्लिम के नाम शामिल होने के मामले हल नहीं हो पाए कि पिता और पति के नाम बदल जाने की शिकायतें आ रही हैं। किसी मतदाता के पिता का नाम बदल गया है तो किसी महिला मतदाता के पति का नाम। इसे सही कराने के लिए मतदाता बीएलओ के चक्कर लगा हैं। शहर के मोहल्ला काशिफ अली सराय में एक ही घर के दो सदस्यों के पिता, पति के नाम बदल दिए गए। मतदाता सूची में यहां रहने वाले सरताज के पिता का नाम शफीक लिख दिया गया है जबकि उनके पिता का नाम मुशीर है। वहीं फरहीन वारसी के पति का नाम नौशाद है। सूची में शफीक अहमद नाम दर्ज कर दिया। दोनों मतदाता दो दिन से नाम सही करवाने के लिए बीएलओ के चक्कर लगा रहे हैं। असोहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मझखोरिया निवासी सुमेर सिंह का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम शामिल था। अब 2025 की अनंतिम मतदाता सूची से नाम कट गया है। इससे वह परेशान हैं। पहले भी कई बार नाम जुड़वाने का प्रयास कर चुके हैं। रविवार को बूथ पर लगे शिविर में फार्म-6 भरकर बीएलओ को दिया है। उधर, मिर्रीकला की मतदाता ममता के पति का नाम बाबू है। जबकि सूची में ममता पत्नी चंद्रभान लिखा है। वह पति का नाम बाबू कराने के लिए बूथ की दौड़ लगा रही हैं। तहसील पुरवा की ग्राम पंचायत कांथा के वार्ड संख्या छह में नसीम परिवार के साथ रहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में उनके परिवार में कांथा मस्जिद में पूर्व में मौलवी रहे इकरामुद्दीन की पत्नी अजमेरुन निशा का नाम शामिल कर दिया गया है जबकि मौलवी पत्नी सहित पिछले लगभग दस वर्षों से बहराइच में रह रहे हैं। अनंतिम मतदाता सूची को लेकर रविवार को लगे शिविरों में दस हजार से अधिक आपत्तियां व दावे आए हैं। इनमें अधिकांश नए नाम शामिल करने की हैं। आपत्तियों व दावों की सूची तैयार कराई जा रही है। अभी तहसीलों से फाइनल लिस्ट नहीं मिली है। जो आपत्तियां, दावे आएंगे, उनका निस्तारण कराया जाएगा। अगला शिविर 31 जनवरी को लगेगा। -आशुतोष मिश्रा, सहायक निर्वाचन अधिकारी।

15000 लोगों को मिलेगी नौकरी, तैयार होंगे हथियार

उन्नाव, (संवाददाता)। उन्नाव जिला अब रक्षा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण साजो-सामान उपलब्ध कराएगा। शासन ने जिले में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उन्नाव को रक्षा उपकरणों के निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सदर तहसील के ग्राम पंचायतों सरांय कटियान, मुर्तजा नगर और ओरहर में 230 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। इस कॉरिडोर में ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे जो हथियार, गोला-बारूद, ड्रोन, मशीन गन, बुलेट और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे सैन्य व रक्षा उपकरण बनाएंगे। यह क्षेत्र पहले से ही राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में शामिल है और यहां इंडस्ट्रियल हब को भी मंजूरी मिल चुकी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह मुर्तजानगर के पास बन रहे इंडस्ट्रियल हब के करीब स्थित होगा। इसकी कानपुर-लखनऊ हाईवे (एनएच-27) से दूरी मात्र दो किलोमीटर, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से करीब 100 मीटर और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे से लगभग 10 किलोमीटर है। यह उत्कृष्ट कनेक्टिविटी देश और प्रदेश के प्रमुख शहरों से सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी। सरकार देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को गति दे रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना उत्तर प्रदेश को भारत के रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जमीन का चयन कर लिया गया है और मार्च तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

डेढ़ महीने बाद कब्र से शव निकाल दोबारा कराया पोस्टमार्टम

उन्नाव, (संवाददाता)। डेढ़ महीने कांशीराम कॉलोनी में युवक का शव फंदे से लटका मिले की घटना में परिजनों की ओर से हत्या के आरोप पर सोमवार को शव को कब्र से निकाल कर तीन डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि दोबारा पोस्टमार्टम में फंदे से लटकने से ही मौत की पुष्टि हुई है। शव पुराना होने से शरीर में किसी तरह की चोट की पुष्टि नहीं हुई है। सदर कोतवाली की कांशीराम कॉलोनी निवासी दिनेश गौतम (32) का शव 30 नवंबर 2025 को घर के कमरे में रस्सी के फंदे से लटका मिला था। दिनेश की मां फूलकुमारी ने आरोप लगाया था कि मजदूरी का पैसा न देना पड़े इसलिए कुछ लोगों बेटे दिनेश को पीटा था फिर गला कसकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उस समय पोस्टमार्टम कराया था जिसमें शरीर पर चोट का कोई निशान न होने और हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़िता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएम गौरांग राठी ने शव के दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। सोमवार सुबह एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी और सीओ सिटी दीपक यादव की मौजूदगी में ईदगाह स्थित कब्रिस्तान से पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया। दोपहर बाद अचलगंज सीएचसी के डॉ. आशुतोष वार्ष्णणेय, सीएचसी हसनगंज के डॉ. रोहित सिंह और सीएचसी मियागंज के डॉ. उमर फारुख ने वीडियोग्रॉफी के बीच शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई, लेकिन शव डेढ़ महीने पुराना होने से किसी तरह की चोट की पुष्टि नहीं हुई। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव शेखपुर नहर के ईदगाह रेलवे लाइन के पास बने कब्रिस्तान से सोमवार सुबह शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर दफ्न करा दिया गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।